International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था का विकास और आर्थिक वृद्धि पर उसका प्रभाव: एक सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. इन्द्र सिंह

अर्थशास्त्र विभाग
दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, रामपुर (उत्तर प्रदेश)

सारांश

वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को तीव्र गति से परिवर्तित कर रही है। भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था का विस्तार केवल सूचना और संचार से संबंधित गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सरकारी सेवाओं तथा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अंकीय भुगतान, एकीकृत भुगतान व्यवस्था, आधार आधारित पहचान, अंकीय बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, अंकीय सरकारी सेवाएँ तथा अंकीय सार्वजनिक आधारभूत संरचना ने आर्थिक गतिविधियों को अधिक तीव्र, सरल और व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक आकलन के अनुसार वर्ष 2022–23 में भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय के 11.74 प्रतिशत के बराबर थी। इसका कुल आकार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर लगभग 31.64 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2024–25 के लिए अंकीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा 13.42 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया था। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा आर्थिक वृद्धि पर उसके प्रभाव का सैद्धांतिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर अध्ययन करना है। अध्ययन में भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अंकीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय समावेशन, भुगतान व्यवस्था, व्यापारिक दक्षता, बाजार विस्तार, रोजगार तथा सरकारी सेवाओं की पहुँच को प्रभावित किया है। साथ ही अंकीय विभाजन, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा, अंकीय कौशल तथा रोजगार के बदलते स्वरूप जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

मुख्य शब्द: अंकीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक वृद्धि, अंकीय भुगतान, वित्तीय समावेशन, अंकीय आधारभूत संरचना, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, रोजगार, भारत

1. प्रस्तावना

इक्कीसवीं शताब्दी में अंकीय प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है। परंपरागत अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, विपणन, भुगतान तथा सेवाओं की उपलब्धता मुख्यतः भौतिक माध्यमों पर निर्भर थी। वर्तमान समय में इन गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा अंकीय माध्यमों के द्वारा संचालित हो रहा है। वस्तुओं और सेवाओं की खोज से लेकर खरीद, भुगतान, वितरण और उपभोक्ता सेवा तक अनेक गतिविधियाँ अब अंकीय माध्यम से की जा सकती हैं। भारत ने पिछले एक दशक में अंकीय परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंकीय भारत

कार्यक्रम, आधार, जन-धन खाते, मोबाइल संचार, अंतरजाल, एकीकृत भुगतान व्यवस्था, अंकीय दस्तावेज भंडारण तथा अन्य सार्वजनिक अंकीय व्यवस्थाओं ने देश में अंकीय सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2014 में भारत में अंतरजाल ग्राहकों की संख्या लगभग 25.1 करोड़ थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 95.4 करोड़ हो गई। इसी अवधि में अंतरजाल घनत्व भी बढ़ा और अंकीय सेवाओं के उपयोग की संभावनाएँ व्यापक हुईं। अंकीय अर्थव्यवस्था का महत्व केवल इस बात से निर्धारित नहीं होता कि कितने लोग अंतरजाल का उपयोग कर रहे हैं। इसका वास्तविक आर्थिक महत्व इस बात में है कि अंकीय तकनीक उत्पादन, व्यापार, वित्तीय लेन-देन, रोजगार, सरकारी सेवाओं और उपभोग की प्रकृति को किस प्रकार बदल रही है। इसी संदर्भ में भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि अंकीय परिवर्तन किस प्रकार आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है और इसके लाभों को व्यापक तथा समावेशी बनाने के लिए किन नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

2. अंकीय अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं स्वरूप

अंकीय अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें अंकीय प्रौद्योगिकी, सूचना, संचार व्यवस्था, अंकीय मंच, अंकीय भुगतान तथा अंकीय सेवाएँ आर्थिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंकीय अर्थव्यवस्था को केवल कंप्यूटर और अंतरजाल आधारित उद्योगों तक सीमित समझना उचित नहीं है। वर्तमान समय में लगभग प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र किसी न किसी रूप में अंकीय तकनीक से प्रभावित है। बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग और अंकीय भुगतान, व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, शिक्षा में अंतरजालीय शिक्षा, स्वास्थ्य में दूरस्थ चिकित्सा, परिवहन में अंकीय सेवाएँ और शासन में अंकीय प्रशासन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था अब केवल सूचना और संचार से संबंधित उद्योगों तक सीमित नहीं है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, व्यापार तथा शिक्षा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में अंकीयकरण का योगदान भी बढ़ रहा है। वर्ष 2022–23 में सूचना एवं संचार से संबंधित सक्षम उद्योगों का सकल मूल्यवर्धन में योगदान 7.83 प्रतिशत था। नई अंकीय उद्योग व्यवस्थाओं का योगदान लगभग 2 प्रतिशत तथा तीन पारंपरिक क्षेत्रों में अंकीय योगदान भी लगभग 2 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट है कि अंकीय अर्थव्यवस्था अब अर्थव्यवस्था के एक छोटे क्षेत्र के बजाय व्यापक आर्थिक संरचना का हिस्सा बन चुकी है।

3. भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था का विकास

भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था का विकास कई चरणों में हुआ है। दूरसंचार के विस्तार, मोबाइल उपकरणों की उपलब्धता, अंतरजाल की बढ़ती पहुँच, कम होती आँकड़ा लागत तथा सरकारी अंकीय पहलों ने इस प्रक्रिया को गति दी है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2014 में अंतरजाल ग्राहकों की संख्या 25.1 करोड़ थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 95.4 करोड़ हो गई। मार्च 2024 में अंतरजाल घनत्व 68.2 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह परिवर्तन भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतरजाल की व्यापक पहुँच से बैंकिंग, भुगतान, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा सरकारी सेवाओं का उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जा सकता है। भारत में अंकीय परिवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण आधार अंकीय सार्वजनिक आधारभूत संरचना है। आधार, एकीकृत भुगतान व्यवस्था, अंकीय दस्तावेज भंडार, इलेक्ट्रॉनिक पहचान तथा अन्य व्यवस्थाओं ने नागरिकों और संस्थाओं के बीच अंकीय संपर्क को सरल बनाने में योगदान दिया है। इस विकास का आर्थिक महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में भौतिक माध्यमों से प्रत्येक नागरिक तक सेवाएँ पहुँचाना कठिन और महँगा हो सकता है। अंकीय माध्यम इस प्रक्रिया की लागत और समय दोनों को कम करने की क्षमता रखते हैं।

4. अंकीय भुगतान व्यवस्था का विकास

भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था के विकास में अंकीय भुगतान व्यवस्था का विशेष महत्व है। एकीकृत भुगतान व्यवस्था ने बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण को अत्यंत सरल बनाया है। छोटे व्यापारी, दुकानदार, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा सामान्य उपभोक्ता इसका उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में एकीकृत भुगतान व्यवस्था के माध्यम से लगभग **13,116.5 करोड़ लेन-देन** हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग **199.9 लाख करोड़ रुपये** था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024–25 में लेन-देन की मात्रा लगभग **18,586.21 करोड़** तक पहुँच गई और कुल मूल्य लगभग **260.56 लाख करोड़ रुपये** रहा। इन आँकड़ों से अंकीय भुगतान की तीव्र वृद्धि स्पष्ट होती है। अंकीय भुगतान के विस्तार का आर्थिक महत्व कई स्तरों पर है। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज होती है, नकद धन पर निर्भरता कम होती है और छोटे व्यापारियों के लिए औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने के अवसर बढ़ते हैं। अंकीय भुगतान से लेन-देन का अभिलेख भी उपलब्ध रहता है। इससे आर्थिक गतिविधियों के औपचारिककरण में सहायता मिल सकती है तथा छोटे व्यवसायों के लिए भविष्य में ऋण प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। इस प्रकार अंकीय भुगतान केवल भुगतान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण और वित्तीय समावेशन का भी महत्वपूर्ण साधन है।

5. अंकीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि

आर्थिक वृद्धि से आशय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में समय के साथ होने वाली वृद्धि से है। अंकीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले, अंकीय तकनीक उत्पादन और व्यापार की दक्षता बढ़ा सकती है। व्यापारिक संस्थाएँ अंकीय माध्यम से ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ अधिक तेजी से संपर्क कर सकती हैं। इससे सूचना प्राप्त करने, भुगतान करने, विपणन करने और संसाधनों के प्रबंधन में लगने वाला समय कम हो सकता है। दूसरे, अंकीय व्यवस्था बाजार का विस्तार करती है। एक छोटा व्यवसाय केवल स्थानीय ग्राहकों तक सीमित रहने के बजाय अंकीय मंचों के माध्यम से दूर के ग्राहकों तक भी पहुँच सकता है। इससे बाजार का आकार बढ़ सकता है और व्यवसाय के विस्तार की संभावना उत्पन्न होती है। तीसरे, अंकीय भुगतान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकता है। जब अधिक लोग औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ते हैं, तो बचत, ऋण, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ सकती है। चौथे, अंकीय प्रशासन सरकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार कर सकता है। इससे प्रशासनिक लागत कम हो सकती है और नागरिकों को सेवाएँ अपेक्षाकृत तेजी से मिल सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आकलन के अनुसार 2022–23 में भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था का आकार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर लगभग **31.64 लाख करोड़ रुपये** था और राष्ट्रीय आय में इसका हिस्सा **11.74 प्रतिशत** था। 2024–25 के लिए इसका हिस्सा **13.42 प्रतिशत** रहने का अनुमान लगाया गया था। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि अंकीय अर्थव्यवस्था भारत की समग्र आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है।

6. अंकीय अर्थव्यवस्था और रोजगार

अंकीय अर्थव्यवस्था ने रोजगार के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। एक ओर सूचना प्रौद्योगिकी, अंकीय विपणन, अंकीय बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, आँकड़ा विश्लेषण और अंकीय सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। दूसरी ओर पारंपरिक कार्यों के कुछ हिस्सों में स्वचालन के कारण रोजगार की प्रकृति बदल रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आकलन के अनुसार 2022–23 में भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था से संबंधित रोजगार लगभग **1.467 करोड़** था, जो कुल कार्यबल का लगभग **2.55 प्रतिशत** था। मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि अंकीय अर्थव्यवस्था का उत्पादकता स्तर शेष अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक रहा। अंकीय अर्थव्यवस्था

ने स्वतंत्र कार्य, मंच आधारित कार्य और घर से काम करने जैसी नई कार्य व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा दिया है। इससे रोजगार के अवसरों में विविधता आई है। लेकिन इसके साथ कौशल संबंधी चुनौती भी उत्पन्न हुई है। जिन श्रमिकों के पास नई तकनीकों का ज्ञान नहीं है, उनके लिए रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकती है। इसलिए अंकीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ कौशल उन्नयन और पुनःकौशल विकास अत्यंत आवश्यक है।

7. अंकीय अर्थव्यवस्था और व्यापार

व्यापार के क्षेत्र में अंकीय परिवर्तन ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीद-बिक्री के तरीके को बदल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के माध्यम से उपभोक्ता अपने घर से विभिन्न वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, उनकी तुलना कर सकता है, खरीदारी कर सकता है और अंकीय भुगतान कर सकता है। अंकीय व्यापार का सबसे बड़ा लाभ बाजार के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। छोटे व्यापारी भी अंकीय मंचों के माध्यम से ऐसे ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं जो भौगोलिक रूप से उनसे बहुत दूर हैं।

अंकीय व्यापार से बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलने से वस्तुओं की गुणवत्ता, कीमत और सेवा के संबंध में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। हालाँकि छोटे व्यापारियों के लिए अंकीय व्यापार अपनाने में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। उन्हें अंकीय कौशल, उत्पाद प्रस्तुति, ग्राहक सेवा, कर संबंधी जानकारी तथा साइबर सुरक्षा का ज्ञान आवश्यक होता है। इसलिए अंकीय व्यापार का विस्तार प्रशिक्षण और संस्थागत सहायता के साथ होना चाहिए।

8. अंकीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों को बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा और भुगतान जैसी वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है। भारत में अंकीय तकनीक ने वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधार आधारित पहचान, बैंक खाते, मोबाइल संचार तथा अंकीय भुगतान के संयोजन ने वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाया है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी भारत की अंकीय सार्वजनिक आधारभूत संरचना को वित्तीय समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अंकीय वित्तीय सेवाएँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को छोटी राशि भेजने या प्राप्त करने के लिए बैंक शाखा तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, तो समय और यात्रा लागत दोनों की बचत होती है। इस प्रकार अंकीय वित्तीय व्यवस्था आर्थिक गतिविधियों में उन वर्गों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता कर सकती है जो पहले औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से सीमित रूप से जुड़े थे।

9. अंकीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास

भारत की बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए अंकीय अर्थव्यवस्था की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव है जब इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँचे। अंतरजाल और मोबाइल संचार की पहुँच बढ़ने से ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संबंधी जानकारी, बाजार मूल्य, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के नए अवसर मिले हैं। भारत सरकार के अनुसार 2024 तक देश में अंतरजाल कनेक्शनों की संख्या लगभग **96.96 करोड़** तक पहुँच चुकी थी। भारतनेट के माध्यम से भी बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों को उच्च गति वाले अंतरजाल से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में अंकीय व्यवस्था किसानों को बाजार भाव, मौसम संबंधी सूचना तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। इसी प्रकार ग्रामीण छोटे व्यवसाय अंकीय माध्यम से नए ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंकीय विभाजन पूरी तरह समाप्त

नहीं हुआ है। केवल इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। नागरिकों में अंकीय साक्षरता, उपकरणों की उपलब्धता, भाषा की सुविधा और साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता भी आवश्यक है।

10. अंकीय अर्थव्यवस्था और सरकारी सेवाएँ

अंकीय तकनीक ने सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित किया है। प्रमाणपत्र, भुगतान, दस्तावेज, आवेदन, शिकायत तथा विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए अंकीय माध्यमों का उपयोग बढ़ा है। अंकीय प्रशासन का एक प्रमुख लाभ समय और लागत में कमी है। यदि नागरिक को किसी सेवा के लिए बार-बार सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसके समय और धन की बचत होती है। भारत में अंकीय दस्तावेज भंडार जैसी व्यवस्थाओं ने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अंकीय रूप में सुरक्षित रखने तथा आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की है। अंकीय सार्वजनिक आधारभूत संरचना ने विभिन्न सेवाओं को परस्पर जोड़ने में भी सहायता की है। सरकार की दृष्टि से अंकीय अभिलेख प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित करने, सेवाओं की निगरानी करने तथा संसाधनों के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकते हैं।

11. अंकीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ

अंकीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। सबसे पहली चुनौती **अंकीय विभाजन** है। समाज के सभी वर्गों के पास समान स्तर की अंकीय सुविधाएँ, उपकरण और कौशल उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती **साइबर अपराध** है। जैसे-जैसे अंकीय भुगतान बढ़ता है, वैसे-वैसे धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और अन्य साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ता है। तीसरी चुनौती **व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा** है। अंकीय अर्थव्यवस्था में व्यक्ति से संबंधित बड़ी मात्रा में सूचना विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध होती है। इस सूचना की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। चौथी चुनौती **अंकीय कौशल की कमी** है। यदि नागरिक अंकीय सेवाओं का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते, तो अंकीय अर्थव्यवस्था का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। पाँचवीं चुनौती रोजगार से संबंधित है। स्वचालन और नई तकनीक कुछ पारंपरिक कार्यों की आवश्यकता कम कर सकती है। इसलिए श्रमिकों को बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप नए कौशल प्राप्त करना आवश्यक है।

12. अंकीय अर्थव्यवस्था का समग्र आर्थिक प्रभाव

उपलब्ध सरकारी आँकड़ों का समग्र अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था का विस्तार तीव्र गति से हुआ है। वर्ष 2014 में लगभग 25.15 करोड़ अंतरजाल कनेक्शन थे, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 96.96 करोड़ हो गए। इसी प्रकार अंकीय अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में योगदान वर्ष 2022–23 में 11.74 प्रतिशत था और 2024–25 के लिए 13.42 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। अंकीय अर्थव्यवस्था से संबंधित रोजगार भी 2022–23 में लगभग 1.467 करोड़ था। इन आँकड़ों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अंकीय परिवर्तन केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है। यह आर्थिक संरचना में व्यापक परिवर्तन का संकेत है। अंतरजाल की बढ़ती पहुँच ने अंकीय सेवाओं के लिए बाजार तैयार किया, अंकीय भुगतान ने आर्थिक लेन-देन को सरल बनाया, अंकीय सार्वजनिक आधारभूत संरचना ने वित्तीय और सरकारी सेवाओं की पहुँच बढ़ाई और अंकीय व्यापार ने बाजारों को अधिक व्यापक बनाया। फिर भी आर्थिक वृद्धि और अंकीय विकास के बीच सीधा कारण-परिणाम संबंध स्थापित करना उचित नहीं होगा। आर्थिक वृद्धि पर निवेश, उपभोग, उत्पादन, निर्यात, मानव पूँजी, सरकारी व्यय और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अंकीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक वृद्धि का अकेला कारण नहीं बल्कि **आर्थिक वृद्धि को गति देने वाला महत्वपूर्ण आधार** माना जाना अधिक उचित है।

13. नीतिगत सुझाव

भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली अंतरजाल सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरे, अंकीय साक्षरता को व्यापक बनाया जाना चाहिए। नागरिकों को केवल मोबाइल या अंतरजाल चलाने की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अंकीय भुगतान, व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव तथा सुरक्षित अंकीय व्यवहार का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। तीसरे, युवाओं के लिए अंकीय कौशल, पुनःकौशल और कौशल उन्नयन के कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिए। इससे बदलती रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमिकों की क्षमता विकसित होगी। चौथे, छोटे और मध्यम व्यवसायों को अंकीय व्यापार अपनाने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पाँचवें, साइबर सुरक्षा को अंकीय अर्थव्यवस्था की मूल आवश्यकता माना जाना चाहिए। नागरिकों और व्यापारिक संस्थाओं को सुरक्षित अंकीय व्यवहार के लिए नियमित जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए। छठे, अंकीय विकास को भारतीय भाषाओं से जोड़ा जाना चाहिए ताकि भाषा की समस्या के कारण कोई वर्ग अंकीय सेवाओं से बाहर न रह जाए।

14. निष्कर्ष

भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था का विकास देश की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। अंतरजाल, मोबाइल संचार, अंकीय भुगतान, अंकीय बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और अंकीय सरकारी सेवाओं ने आर्थिक गतिविधियों को अधिक तेज और व्यापक बनाने में सहायता की है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 2022–23 में भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय के 11.74 प्रतिशत के बराबर थी तथा इसका आकार लगभग 31.64 लाख करोड़ रुपये था। 2024–25 के लिए इसका हिस्सा 13.42 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया था। अंतरजाल कनेक्शनों की संख्या में हुई वृद्धि भी अंकीय परिवर्तन की व्यापकता को दर्शाती है। वर्ष 2014 में लगभग 25.15 करोड़ अंतरजाल कनेक्शन से बढ़कर वर्ष 2024 में यह संख्या 96.96 करोड़ हो गई। अंकीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय समावेशन, बाजार विस्तार, व्यापारिक दक्षता, सरकारी सेवा वितरण और रोजगार के नए अवसरों में योगदान दिया है। साथ ही अंकीय विभाजन, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा और कौशल संबंधी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। अतः भारत के लिए भविष्य की आर्थिक नीति का उद्देश्य केवल अंकीय तकनीक का विस्तार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी **समावेशी, सुरक्षित, सुलभ और कौशल-आधारित अंकीय अर्थव्यवस्था** का निर्माण करना होना चाहिए जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँच सके। यदि अंकीय आधारभूत संरचना के साथ मानव संसाधन विकास, अंकीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा और समावेशी नीतियों को समान महत्व दिया जाता है, तो अंकीय अर्थव्यवस्था भारत की दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि और विकास का एक मजबूत आधार बन सकती है।

15. अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों तथा सैद्धांतिक विवेचन पर आधारित है। इसमें प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः अंकीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध स्थापित करने का दावा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, अंकीय अर्थव्यवस्था के आँकड़ों की गणना के लिए विभिन्न संस्थाएँ अलग-अलग परिभाषाओं और पद्धतियों का प्रयोग कर सकती हैं। इसलिए विभिन्न स्रोतों के आँकड़ों की तुलना करते समय उनकी परिभाषा और गणना पद्धति को ध्यान में रखना आवश्यक है।

16. भविष्य के अध्ययन की संभावनाएँ

भविष्य में इस विषय पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की तुलना की जा सकती है। विभिन्न राज्यों में अंकीय भुगतान की वृद्धि तथा राज्य की आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध का अध्ययन भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अंकीय अर्थव्यवस्था का छोटे व्यापारियों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और स्वरोजगार पर प्रभाव अलग-अलग अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है। अंकीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के संबंध में भी अधिक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, विशेष रूप से स्वचालन, मंच आधारित कार्य और नए कौशल की माँग के संदर्भ में।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था का आकलन एवं मापन।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25।
4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26।
5. राष्ट्रीय भुगतान निगम। एकीकृत भुगतान व्यवस्था के आँकड़े।
6. भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो। अंकीय भारत की प्रगति संबंधी आधिकारिक आँकड़े।
7. नीति आयोग। भारत की मंच आधारित अर्थव्यवस्था एवं रोजगार संबंधी अध्ययन।
8. विश्व बैंक। अंकीय सार्वजनिक आधारभूत संरचना एवं सेवाएँ।
9. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अंकीय अर्थव्यवस्था के मापन संबंधी अध्ययन।
10. भारत सरकार। अंकीय भारत कार्यक्रम संबंधी आधिकारिक सामग्री।